सम्पूर्ण आजादी का दस्तावेज

डाईवर्सिटी

इयर बुक : 2014-15

संपादक : एच.एल. दुसाध

सह-संपादक : कविश कुमार–जनार्दन

डाइवर्सिटी इयर-बुक

2014-15

सम्पादक

एच.एल. दुसाध

सह-सम्पादक

कविश कुमार

जनार्दन

दुसाध प्रकाशन

लखनऊ

प्रथम संस्करण : 2014

ISBN : 978-81-87618-51-5

प्रकाशक : **दुसाध प्रकाशन**
प्लाट नं. 23/बी, मकान नं. 2/1467,
डाइवर्सिटी हाउस, वार्ड-शंकरपुरवा
आदिल नगर, कल्याणपुर, लखनऊ-226022
E-mail : hl.dusadh@gmail.com
मो. : 9654816191, 9696252469

प्रशासनिक कार्यालय
एफ-196, आया नगर एक्स, फेज-6, नई दिल्ली-110047,
मो. : 9313186503

© **संपादक**

मूल्य : 2000.00 रुपये

रचना	:	**डाइवर्सिटी इयर-बुक : 2014-15**
संपादक	:	एच.एल. दुसाध
आवरण	:	शशिकान्त
शब्दांकन	:	कम्प्यूटेक सिस्टम, शाहदरा, दिल्ली-32
मुद्रक	:	क्वालिटी प्रिंटर्स, दिल्ली-32

डाइवर्सिटी इयर बुक

2014-15 का संपादकीय परिवार

संरक्षक	:	**डॉ. संजय पासवान**
प्रेरणा मण्डल	:	**दिग्विजय सिंह, चन्द्रभान प्रसाद, सुधीन्द्र कुलकर्णी, डॉ. जगदीश प्रसाद, छेदी पासवान, डॉ. उदित राज, डॉ. नन्दू प्रसाद, डॉ. एस. एन. संखवार, डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल, सुरेश केदारे, डॉ. संजय वठारे, इंजी. हरिकेश्वर राम**
मुख्य परामर्शदाता	:	**बुद्ध शरण हंस, दिलीप मंडल**
परामर्श मण्डल	:	**बृजपाल भारती, डॉ. विजय कुमार त्रिशरण, इंजी. केदार पासवान, अभिजीत कुमार, सुदेश तनवर, डॉ. पी. एल. संखवार, आर.सी. भाष्कर, आशिक भागलपुरी, कौशलेन्द्र प्रताप यादव, नागेन्द्र कुमार, निर्मल पासवान**
संपादक	:	**एच.एल. दुसाध**
सह-संपादक	:	**कविश कुमार, जनार्दन**
संपादक मण्डल	:	**शीलबोधि, डॉ. चन्द्रशेखर राम, ललन कुमार, अनिल कुमार आर्य, राम किशोर यादव, डॉ. अमरनाथ, बाबूलाल मधुकर, श्रवण कुमार पासवान**
संपादकीय संपर्क	:	**एच.एल. दुसाध** एफ-196, आया नगर एक्स, फेज-6 नई दिल्ली-110047 मो. 9654816191, 9696252469

समर्पण

भारतीय राजनीति की विरल प्रतिभा

डॉ. उदित राज *को*

जिन्होंने अनुसूचित जाति-जनजाति

संगठनों के अखिल भारतीय परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के

रूप में वंचितों की भागीदारी की

लड़ाई का उज्जवलतम दृष्टान्त

प्रस्तुत किया है।

सम्पादकीय

निर्दिष्ट तिथि पर 'डाइवर्सिटी डे' आयोजित करने में फिर विफल : बीडीएम

2006 से शुरू हुई डाइवर्सिटी इयर बुक का यह नवा अंक है जिसे विगत तीन वर्षों की भांति इस बार भी निर्दिष्ट तिथि (27 अगस्त) पर लाने में संपादक मंडल व्यर्थ रहा है। इसका कारण यह है कि जिस 'डाइवर्सिटी डे' के अवसर पर इसका प्रकाशन होता है,विविध कारणों से हम 2011 से ही उसका निर्दिष्ट तिथि ,27 अगस्त पर आयोजन करने में नाकाम रहे हैं। 2011 में 16 अक्तूबर,2012 में 30 सितम्बर और 2013 में इसका आयोजन 8 नवम्बर को हुआ। इस बार भी बीडीएम के लोग 2011 के पूर्व की भांति 27 अगस्त को डाइवर्सिटी डे आयोजित करने में सफल नहीं हो पाए। बहरहाल देर से ही सही पाठकों के बीच इयर बुक का जो नया अंक पहुंच रहा है, वह डाइवर्सिटी इयर बुक के इतिहास का दूसरा चुनावी विशेषांक है। पहली बार ऐसा खास अंक 2009 में प्रकाशित हुआ था जब डाइवर्सिटी इयर बुक : 2009-10 में लोकसभा चुनाव-2009 को लगभग 350 पृष्ठों में कवर किया गया था,जबकि सोलहवीं लोकसभा चुनाव के लिए इस बार लगभग 500 पृष्ठ खर्च हुए हैं।

चुनावों में बीडीएम की सक्रियता

बहरहाल जब भी लोकसभा या विधान सभा चुनावों की घोषणा होती है,छोटे-छोटे संगठन राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में अपने मुद्दे शामिल करवाने के लिए सक्रिय हो उठते हैं। इस लिहाज से देखा जाय तो बहुजन लेखकों द्वारा 2007 में स्थापित 'बहुजन डाइवर्सिटी मिशन' (बीडीएम) कुछ ज्यादे ही सक्रिय रहा। ऐसा इसलिए कि संगठन के एजेंडे को लागू करवाने के लिए इसकी घोषित स्ट्रेटजी पार्टियों के घोषणा पत्रों में डाइवर्सिटी को शामिल करवाने की ही रही है। बीडीएम की स्थापना के बाद पहला महत्त्वपूर्ण चुनाव 2009 का 15 वीं लोकसभा चुनाव रहा। उसमें प्रचुर लेखन के साथ संगठन के तरफ से ढेरों सेमिनार आयोजित कर पार्टियों का ध्यान डाइवर्सिटी की ओर आकर्षित किया गया। परिणाम खूब निराशाजनक नहीं रहा। भाजपा जैसी

बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के घोषणा पत्र में डाइवर्सिटी को जगह मिली।

2009 में मिली आंशिक सफलता से उत्साहित होकर बीडीएम की ओर से बिहार विधान सभा चुनाव-2010 में कुछ अतिरिक्त प्रयास किया गया। इसके तहत सबसे पहले 15 मार्च को आयोजित होने वाले संगठन के स्थापना दिवस को पटना में आयोजित किया गया और चर्चा का विषय रखा गया 'बिहार विधान सभा चुनाव -2010 और डाइवर्सिटी।' उसके महीने भर के अन्दर इसी आशय से 11-16 अप्रैल, 2010 तक छः दिवसीय जनचेतना यात्रा निकाल कर भागलपुर, बांका और मुंगेर में 18 सभाएं आयोजित की गयीं। अगले चरण में फिर 27 अगस्त को पटना में ही 'डाइवर्सिटी डे ' का आयोजन कर तमाम पार्टियों को उनके घोषणा पत्रों में डाइवर्सिटी को जगह देने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। लेकिन संगठन से जुड़े लोग इतने से संतुष्ट नहीं थे। लिहाजा संगठन की ओर से चुनाव प्रचार के दौरान मुझे पूरे बिहार की यात्रा कर जनता के माध्यम से राजनीतिक दलों पर दबाव बनाने का कार्य सौंपा गया। चुनाव प्रचार थमते-थमते मैंने बिहार के 18 जिलों की यात्रा पूरा कर लिया। यात्रा के दौरान जिला मुख्यालयों में पहुँच कर प्रेस कांफ्रेंस किया। प्रेस कांफ्रेंस में मैं डाइवर्सिटी की घोषणा पत्रों में शामिल करवाने की जरुरत बतलाता। मुझ पर दिल्ली के लेखक-पत्रकार का टैग लगे होने के कारण स्थानीय अखबारों का भरपूर सहयोग मिला। अठारहों जिलों में मेरी प्रेस रिलीज बहुत प्रमुखता से छपी। इससे बड़ी आसानी से निकटवर्ती तीन-चार जिलों में बीडीएम का सन्देश जनता तक पहुँच जाता। यही नहीं अठारहों जिले में प्रेस कांफ्रेंस करने के साथ ही वहां के दलित छात्रावासों में गया। वहां उनको संबोधित करता और 5-7 सौ की मात्रा में चुनाव पर तैयार छः पेज के पर्चे थमा देता। बीडीएम का प्रयास व्यर्थ नहीं गया। डाइवर्सिटी भाजपा के अतिरिक्त एकाध अन्य दलों को भी कुछ आकर्षित की। 2010 के बाद 2012 के यूपी विधान सभा चुनाव में संगठन की ओर से कोई भी प्रयास नहीं हुआ। किन्तु बीजेपी के घोषणा पत्र में डाइवर्सिटी कुछ हद तक बरकरार रही।

लोकसभा चुनाव -2014 में फिर सक्रिय हुआ : बीडीएम

किन्तु लोकसभा चुनाव -2014 को ध्यान में रखकर बीडीएम एक बार फिर सक्रिय हुआ। इसलिए नवम्बर 2013 में जब 'आठवें डाइवर्सिटी डे' का आयोजन दिल्ली के जेएनयू में हुआ, अगले लोकसभा चुनाव में डाइवर्सिटी को शामिल करवाने के लिए चर्चा का विषय रखा गया 'लोकसभा चुनाव-2014 और डाइवर्सिटी' । इस पर चर्चा करवाने के लिए प्रो. वीरभारत तलवार, सुरेश पंडित, प्रो. रमेश दीक्षित, अरुण कुमार त्रिपाठी, शीलबोधि, डॉ. लालजी प्रसाद 'निर्मल', बृजपाल भारती, अनुप्रिया पटेल और डॉ. उदित राज जैसे जाने माने विद्वानों, एक्टिविस्टों और नेताओं को आमंत्रित

किया गया। उस अवसर पर यूं तो 'डाइवर्सिटी इयर बुक : 2013-14', 'जाति उन्मूलन : मार्क्सवादी बनाम आंबेडकरवादी परियोजना' और 'मंडल-3...' जैसी महत्त्वपूर्ण किताबों का विमोचन हुआ, किन्तु जिसे सर्वाधिक गुरुत्व दिया गया वह था एक 6 पृष्ठीय एक फोल्डर, जिसका शीर्षक था–'लोकसभा चुनाव-2014 के मुद्दे और डाइवर्सिटी।' सोलहवी लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में डाइवर्सिटी केन्द्रित दस सूत्रीय एजेंडा शामिल करवाना क्यों आवश्यक है, इसकी बलिष्ठ युक्ति बीडीएम के तरफ से उस फोल्डर में प्रस्तुत करते हुए शेष में लिखा गया था–

'2014 के पूर्वार्द्ध में अनुष्ठित होने वाले लोकसभा चुनाव के पूर्व केंद्र की सत्ता दखल का सेमी-फाइनल माने-जाने वाले पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में जिस तरह राहत और भीखनुमा घोषणाओं की होड़ मची है,उसे देखते हुए दावे के साथ कहा जा सकता है कि 15 वीं लोकसभा की भांति 16 वीं लोकसभा चुनाव में भी मुफ्त में अनाज, रेडियो-टीवी-कंप्यूटर-कुकिंग गैस-साइकल,नकद राशि इत्यादि का प्रलोभन देकर वोट खरीदने का उपक्रम चलाया जायेगा। ऐसा करके राजनीतिक दल हमारे लोकतंत्र को विस्फोटित करने का कुछ और सामान जमा करेंगे। बहरहाल आज जबकि आजाद भारत के शासकों द्वारा शक्ति के स्रोतों में विविधता की अनदेखी के कारण देश में लोकतंत्र के विस्फोटित होने लायक प्रचुर सामान जमा हो चुका है तथा अगले लोकसभा में उसमें कुछ और इजाफा होने जा रहा है,हम क्या करें कि सोलहवीं लोकसभा चुनाव में ही लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया तेज हो। इस दिशा में बहुजन लेखकों द्वारा स्थापित 'बहुजन डाइवर्सिटी मिशन' के दस सूत्रीय एजेंडे से प्रेरणा लेकर राजनीतिक दलों को आर्थिक और सामाजिक विषमता के खात्मे तथा लोकतंत्र की सलामती पर अपने घोषणापत्रों को केन्द्रित करने के लिए दबाव बनाया जा सकता है।'

2013 के शेष तक विगत पांच-छः वर्षों में बीडीएम की ओर से प्रचार-प्रसार का जो अनवरत अभियान चला उससे धीरे-धीरे ढेरों आंबेडकरवादी संगठनों के एजेंडे में घुमा फिराकर डाइवर्सिटी की बात आ गयी थी। इस समय तक सोशल मीडिया से भारी संख्या में उन समाजों के लोग जुड़ चुके थे, जिन्हें डाइवर्सिटी की बहुत जरुरत है। ऐसे में संगठन की ओर से फिल्ड में उतर कर डाइवर्सिटी को घोषणा पत्रों में शामिल करवाने के बजाय, लेखन के माध्यम से इस काम को अंजाम देने का निर्णय लिया गया। उसके बाद संगठन से जुड़े विभिन्न लेखक अपने-अपने तरह से इस काम में लग गए। मैं भी पीछे नहीं रहा।

भाजपा के घोषणा पत्र में डाइवर्सिटी को नहीं मिली जगह

सोलहवीं लोकसभा चुनाव में डाइवर्सिटी एक बड़ा मुद्दा बने, इसके लिए मैंने नवम्बर-2013 से जो प्रयास किया, इस पुस्तक का पहला अध्याय उसका साक्ष्य वहन करता है।

आठवें डाइवर्सिटी डे पर जारी फोल्डर की सामग्री को आधार बनाकर मैंने असंख्य लेख लिखे व अपील जारी किया पर,परिणाम शून्य रहा। मुझे सभी दलों से तो नहीं कम से कम भाजपा के एजेंडे में डाइवर्सिटी के आने की पर्याप्त उम्मीद थी। क्योंकि इस दल ने लोकसभा चुनाव-2009,बिहार विधानसभा चुनाव-2010 और यूपी विधानसभा चुनाव-2012 के अपने घोषणा पत्रों में कमोबेश लगातार इसे जगह दिया था। किन्तु जब डॉ. उदित राज, राम विलास पासवान, उपेन्द्र कुशवाहा, अनुप्रिया पटेल, छेदी पासवान, राम कृपाल यादव, जनक चमार ने गोधरा के लिए कुख्यात नरेंद्र मोदी की राजनीतिक अस्पृश्यता दूर कर दिया तब भाजपा की विजय सुनिश्चित देखते हुए उसकी नीयत के प्रति शंकित होने लगा। पढ़ें अध्याय 2- ए का मेरा लेख-'क्या भाजपा के घोषणा पत्र में बरकरार रहेगा डाइवर्सिटी का मुद्दा!' भाजपा को लेकर मेरी आशंका सही साबित हुई। उसने भी अपने घोषणा पत्र में डाइवर्सिटी को जगह नहीं दिया।

वजूद में आई डाइवर्सिटी समर्थक संख्यानुपाती भागीदारी पार्टी

विगत वर्षों में डाइवर्सिटी के लिए जो अक्लांत प्रयास किया गया , सोलहवें लोकसभा चुनाव में उस पर राजनीतिक दलों की चुप्पी देखकर बीडीएम के लोग पूरी तरह निराशा में डूब जाते,पर 'संख्यानुपाती भागीदारी पार्टी'(संभापा) ने हमें बचा लिया। संभापा वह नई पार्टी थी जिसका निर्माण 2013 में बीडीएम के एजेंडे पर हुआ। इस पार्टी ने यूं तो प्रयोग के तौर पर बिहार में महज चार-पांच ही प्रार्थी ही चुनाव में उतारे, पर इससे जुड़े लोगों ने बता दिया है कि इस देश में कोई तो दल है जो बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर द्वारा 25 नवम्बर 1949 को संसद के केन्द्रीय कक्ष में दी गयी चेतावनी को ध्यान में रखते हुए लोकतंत्र को विस्फोटित होने से बचाने की दिशा में कुछ ठोस काम करना चाहता है। इसलिए ही हमने एक लेख लिख कर संभापा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सूर्योदय पासवान को भीम सलाम नजर किया है। चूँकि बाकी दलों ने आर्थिक और सामाजिक गैर-बराबरी,जोकि मानव जाति की सबसे बड़ी समस्या है तथा जिसकी सर्वाधिक व्याप्ति भारत में है, के खात्मे की दिशा में कोई ठोस कार्यक्रम प्रस्तुत ही नहीं किया इसलिए मुझे यह कहने के लिए बाध्य होना पड़ा है कि सोलहवां लोकसभा चुनाव भारतीय लोकतंत्र के ध्वंस की दिशा में एक और कदम मात्र है । बहरहाल भले ही लोकसभा चुनाव-2014 लोकतंत्र के ध्वंस की दिशा में एक और कदम हो किन्तु इसमें कोई शक नहीं कि यह चुनाव कथित नीची जाति के नरेंद्र मोदी के नाम रहा। इसमें भाजपा नहीं, मोदी की ऐसी सुनामी चली कि तमाम विपक्षी दल क्षत-विक्षत हो गए।

मोदी की सुनामी में उड़ी कांग्रेस

वैसे तो मोदी की सुनामी में पूरा विपक्ष ही तहस-नहस हो गया। किन्तु जो दल सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ, वह 128 साल पुरानी व स्वाधीन भारत में सुदीर्घतम समय तक केंद्र की सत्ता पर काबिज रहने वाली कांग्रेस थी। इसीलिए जब 16 मई को कांग्रेस की अकल्पनीय हार का चुनाव परिणाम सामने आया, कई राजनीतिक विश्लेषकों को यह कहने में झिझक नहीं हुई कि मोदी की सुनामी ने कांग्रेस को आई. सी. यू. में पहुंचा दिया है। हार-जीत की आदी रही पार्टी की इस बार के चुनाव परिणामों ने जान ही निकाल दी है और वो दर्द से छटपटाते सांसों के लिए हांफ रही है। इसी तरह राजनीति के कुछ पंडितों ने जहाँ इसके भविष्य में टूटने की सम्भावना जता दी, वहीं कईयों ने कांग्रेस के रूप में एक राजनीतिक युग के अंत की घोषणा कर डाला। यही नहीं सभी टिपण्णीकारों ने एक स्वर में राहुल गाँधी की क्षमता पर सवाल उठाते हुए, पार्टी की हार के लिए व्यक्तिगत तौर पर उन्हें ही जिम्मेवार ठहराया। कुछ ने पार्टी का वजूद बचाए रखने के लिए प्रियंका गाँधी को नेतृत्व सौंपने का सुझाव भी दे डाला।

चुनाव परिणाम आने के एक डेढ़ महीने बाद जब विभिन्न प्रान्तों के स्थापित कांग्रेसी स्थानीय नेतृत्व के खिलाफ बगावत के जरिये राहुल गांधी को खारिज करने का परोक्ष अभियान शुरू कर दिए,उनकी देखादेखि राजनीति के पंडितों में भी उन्हें खारिज करने की होड़ मच गयी। देश के साधारण से लेकर असाधारण कहे जाने वाले तमाम राजनीतिक विश्लेषक जिस तरह राहुल गांधी को नकारने की प्रतिद्वंदिता में उतरे, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि या तो उनकी हैसियत एक रिपोर्टर जैसी है या वे शार्ट टर्म मेमोरी के शिकार हैं। मुझे तो वे मुख्यतः शार्ट टर्म मेमोरी के ही शिकार लगते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो वे यह कैसे भूल जाते कि जिस राहुल गांधी को वे खारिज कर रहे हैं, उसी राहुल को उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में आज के नरेंद्र मोदी की भांति ही तरह से सराहा था। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की निश्चित हार को जीत में बदल कर वह राजनीति के पंडितों की नजरों में एक परिपक्व व करिश्माई नेता बन गए थे। उस चुनाव के बाद लोग राहुल गांधी में पंडित नेहरु का अक्स देखने लगे थे। दरअसल देश के राजनीतिक विश्लेषकों ने शायद कहीं से मान लिया था कि संप्रग-2 का कार्यकाल भी चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त है। अगर इन्होंने अपने मस्तिष्क को जरा भी सक्रिय रखा होता तो उन्हें 2009 में ही कांग्रेस की जीत से हैरानी होती। ऐसे में सोलहवीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार से न तो वे विस्मित होते और न ही हार के लिए राहुल को जिम्मेवार ठहराते हुए उन्हें खारिज करने की बालसुलभ हरकत करते। बहरहाल देश के तमाम राजनीतिक दलों का रंग-ढंग देखते हुए कांग्रेस के दुश्मन भी नहीं चाहेंगे कि यह

पार्टी खत्म हो। इसी तरह चूंकि राहुल गाँधी को ही इस पार्टी को नेतृत्व देना है,इसलिए कोई भी लोकतंत्र प्रेमी नहीं चाहेगा कि वह चिरकाल के लिए ट्रेजडी नायक बन जायें। ऐसे में कांग्रेस और राहुल गाँधी का पुनरुद्धार कैसे हो, इस पर गहराई से विचार करना हर बुद्धिजीवी का अत्याज्य कर्तव्य बनता है। हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया है। इस दिशा में इस पुस्तक के अध्याय 3-बी में छपे मेरे लेख पर्याप्त सामान मुहैया कराएँगे, ऐसी मेरी धारणा है।

आप : भारतीय राजनीति का लाइलाज वायरस

मोदी की सुनामी ने आप विरोधियों को भी जश्न में डूबने का भरपूर अवसर दे दिया। कारण, पिछले वर्ष ही भूमिष्ठ हुई 'आप' ने गत वर्ष दिल्ली में चौकाने वाला परिणाम देकर बहुतों की नीदें उड़ा दी थी। इसीलिए इसके विरोधी सोलहवें लोकसभा चुनाव में भी चौकाने वाले परिणाम को लेकर त्रस्त थे। किन्तु जब परिणाम सामने आया तो पता चला कि राजनीति की 'वंडर' आप भी मोदी की सुनामी की चपेट में आ गयी है। उसका गढ़ माने जाने वाली दिल्ली में उसे एक भी सीटें नहीं मिली। देश की राजनीति की दिशा तय करने वाले उत्तर प्रदेश की 77 सीटों पर मुकाबला करके भी यह पार्टी 1 प्रतिशत वोट तक सीमित रही और इसके अधिकांश उम्मीदवारों के लिए जमानत बचाना कठिन हो गया। उप्र में आप विरोधियों के लिए यह परिणाम भारी संतोषप्रद रहे यह देखते हुए कि केजरीवाल-योगेन्द्र यादव को छोड़कर शाजिया इल्मी, गोपाल राय, आशुतोष, कुमार विश्वास, मनीष सिसोदिया जैसे उसके अन्य कद्दावर नेता इसी प्रदेश से थे। इस चुनाव में मेधा पाटकर, गुल पनाग, योगेन्द्र यादव, आशुतोष, प्रो. साधू सिंह, भगवंत सिंह मान और खुद केजरीवाल जैसे स्टार नेता भी चुनाव हार गए।

किन्तु 'आप' की करारी हार से पुलकित होने वालों को यह नहीं भूलना होगा कि पंजाब से से चार सांसद जुटाने तथा दिल्ली में दूसरे स्थान पर रहने वाली यह पार्टी पूरे देश में 2.1 प्रतिशत वोट प्राप्त कर आरजेडी,जदयू, बीजूजेडी, डीएमके, सीपीआई और एनसीपी जैसे पुराने दलों को पीछे छोड़ कर खतरे की घंटी बजा दी है। इस पार्टी का न्यूनतम लक्ष्य सोलहवी लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करना था,जो मोदी की सुनामी के कारण पूरा न हो सका। पर बहुजन नजरिये से यह पार्टी एक 'लाइलाज राजनीतिक वायरस' के रूप में जन्म ले चुकी है, जिसका भविष्य में मुकाबला करना निश्चय ही स्थापित मनुवादी दलों के मुकाबले कठिन होगा। यही है वह सबसे डेंजरस सवर्णवादी दल जिसके पीछे मीडिया, फिल्म, कारपोरेट, शैक्षिक व बौद्धिक जगत से जुड़े टैलेंटेड लोग तन-मन-धन से लामबंद हैं। बहुजन भारत के लिये सबसे बड़ा खतरा बन चुके इस लाइलाज वायरस को लोग कमतर करके न आंकने लगे, इसके लिए हमने 4-ए में उसके उभार पर एक अध्याय ही रखा

गया है, जिसके साथ अपनी टिप्पणियों को भी जगह दिया है।

बहरहाल 'आप' के वजूद पर कहीं से संकट नहीं है। हाँ खतरा वाम दलों के वजूद पर जरुर है। वाम दलों के भविष्य पर अपनी ओर से कुछ टिपण्णी न कर बस अध्याय 4-सी में छपे तीनों लेख मनोयोग पूर्वक पढने का आग्रह करता हूँ। वाम पंथ की तरह इस बार की मुस्लिम राजनीति की बदतर स्थिति पर कुछ न कह कर बस इतना कहूँगा कि जब चुनाव विभिन्न तबकों के मध्य शक्ति के स्रोतों के बंटवारे पर केन्द्रित न होकर धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर लड़ा जायेगा, उसके दो ही परिणाम सामने आएंगे। पहला, भाजपा के पक्ष में वोटों की बरसात होगी जिसकी कुछ बूंदे छिटक कर लालू-मुलायम जैसों की थाली में भी चली जाएगी। दूसरा परिणाम मुस्लिम राजनीति के कमजोर पड़ने के ही रूप में सामने आयेगा। अतः कह सकता हूँ मुस्लिम राजनीति की वर्तमान दुरावस्था के लिए जिम्मेवार मुख्य रूप से मुलायम लालू जैसे धर्मनिरपेक्षता के झंडाबरदार ही हैं।

सामाजिक न्याय की हार : 2009 में तैयार पटकथा का परिणाम

बहरहाल बहुजन नजरिये से मोदी की सुनामी का जो सबसे पीड़ादायक असर सामने आया वह सामाजिक न्याय की राजनीति के लगभग निर्णायक पतन के रूप में सामने आया है। वैसे तो सुनामी में तब्दील हुई मोदी की आंधी में वाम मोर्चे के साथ महाराष्ट्र में शरद पवार,तमिलनाडु में करूणानिधि जैसे कई क्षेत्रीय दलों और क्षत्रपों का सफाया हो गया,किन्तु राष्ट्रीय राजनीति को सार्वाधिक प्रभावित करने वाले हिंदी पट्टी के यूपी-बिहार जैसे दो राज्यों में जिस तरह लालू-नीतीश,माया-मुलायम-अजित सिंह जैसे सामाजिक न्याय के नायक/नायिकाओं का सफाया हुआ,वह सोलहवीं लोकसभा चुनाव का सबसे चौकाऊ पक्ष रहा। इनमें सबसे अधिक किसी को नुकसान ,उठाना पड़ा तो वह 'बसपा' है। उसकी नुमाइंदगी के लिए एक भी व्यक्ति संसद में नहीं पहुँच पाया। बसपा जैसी राष्ट्रीय पार्टी की करारी हार से जहां जातिवाद से त्रस्त बुद्धिजीवी भारतीय राजनीति में जातिवाद के अंत की शुरुआत मानकर आह्लादित हैं वहीं सामाजिक न्याय के पक्षधर काफी सदमे में हैं। कारण यही वह पार्टी है जिसने जातिवाद का ऐसा गेम खेला जो भारत में सामाजिक परिवर्तन का बड़ा कारण बन सकता था। स्मरण रहे भारत में वर्ण-व्यवस्था के अर्थशास्त्र के तहत शक्ति के स्रोतों से बहिष्कृत कर अशक्त बनाई गयी जातियों की बेहतरी के लिए कुछ करना/कहना मुख्यधारा के लोगों द्वारा जातिवाद के के रूप में निन्दित होता रहा है। बहरहाल लाख टके का सवाल है कि मायावती ही नहीं,लालू-मुलायम इत्यादि सामाजिक न्याय के महानायकों की हार क्या कहीं से चौकाने वाली बात रही ?

नहीं! सोलहवीं लोकसभा चुनाव में इनकी जबरदस्त हार की स्क्रिप्ट 15 वीं लोकसभा चुनाव में ही तैयार हो गयी थी। जाति चेतना के चलते महाबली बने सामाजिक

न्याय के नायक/नायिका पीएम बनने की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के चलते 15 वीं लोकसभा के बहुत पहले से ही जाति-मुक्त बनने की कवायद करने लगे थे। इसके लिए एक ओर जहाँ 'तिलक-तराजू... भूराबाल... 'जैसे जोशीले नारों से पल्ला झड़ने लगे, वहीं दूसरी ओर बहुजनों की सर्वत्र भागीदारी की बात छोड़कर गरीब सवर्णों को आरक्षण दिलाने में एक दूसरे से होड़ लगाने लगे। समाज के प्रति इस विश्वासघात से क्षुब्ध बहुजन समाज ने उन्हें 2009 में ही अर्श से फर्श पर पटक दिया। अर्थात 5 वर्ष पूर्व ही इनके पतन का रिहर्सल हो गया था। इस बात की पुष्टि अध्याय 2-ए में छपा मेरे लेख 'संकट में सामाजिक न्याय की राजनीति' का निम्न अंश करता है जो मैंने किसी को उद्धृत करते हुए लिखा था। जिसको उद्धृत किया था उन्होंने लोकसभा चुनाव में सामाजिक न्याय की राजनीति की घोर पराजय पर भारी अफसोस जताते हुए 2009 में ही लिखा था—

'लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान,मायावती और यूपी में सबसे अधिक सीटें जीतने के बावजूद मुलायम सिंह यादव-ये सभी महारथी इस चुनाव में अपनी चमक खो चुके हैं। इसके साथ ही भारतीय राजनीति व्यवस्था में वंचित समूहों की हिस्सेदारी बढाने की जो प्रक्रिया लगभग 20 साल पहले शुरू हुई, उस मॉडल के नायक-नायिकाओं से राजनीति के जिस मॉडल की बागडोर संभालने की अपेक्षा की जा रही थी और इनके जनाधार की जो महत्वाकांक्षाएं थीं, उसे पूरा करने में ये सभी नाकाम हो चुके हैं। यह एक सपने के टूटने की दास्तान है। यह सपना था भारत को बेहतर और सबकी हिस्सेदारी वाला लोकतंत्र बनाने का और देश के संसाधनों पर खासकर वंचित समूहों की हिस्सेदारी दिलाने का।'

उपरोक्त टिपण्णी, जिसमें उन दिनों अधिकांश सामाजिक न्याय समर्थक बुद्धिजीवियों की भावनाओं का ही जबरदस्त प्रतिबिम्बन हुआ था,बताती है कि पिछले लोकसभा चुनाव में ही सामाजिक न्याय की राजनीति आभाहीन हो गयी थी तथा इससे जुड़े नायक-नायिकाओं का निर्णायक तौर पर पतन हो गया था। उसके बाद उनके पास सोलहवीं लोकसभा चुनाव में विजय हासिल करने का एक ही उपाय था कि वे भारत के लोकतंत्र को सबकी हिस्सेदारी वाला लोकतंत्र बनाने तथा देश के संसाधनों पर वंचित समूहों की हिस्सेदारी दिलाने का जोरदार अभियान चलाते जो उन्होंने बिलकुल ही नहीं किया। अतः यह दावे से कहा जा सकता है सामाजिक न्याय के नायक/नायिकाओं की शर्मनाक पराजय के लिए जिम्मेवार मोदी की सुनामी नहीं, बहुजनवाद से विचलन है। अब लाख टके का सवाल है क्या इनका पुनरुद्धार होगा? मेरा मानना है 'नहीं'। कारण, 16 मई के बाद का इनका चाल-चलन बता रहा है कि इन्होंने सामाजिक न्याय की राजनीति की ताबूत में अंतिम कील ठोकने का फैसला कर लिया है। क्योंकि ये अपने एजेंडे को पूरी तरह सवर्णपरस्ती पर कायम रखने के प्रति अडिग हैं। बसपा हो या सपा कोई भी भारतीय लोकतंत्र को सबकी

हिस्सेदारी वाला लोकतंत्र बनाने तथा देश के संसाधनों पर वंचित समूहों की हिस्सेदारी के प्रति नाम मात्र भी इच्छुक नहीं है। हालांकि इस बीच लालू ने कमंडल की काट मंडल में बता कर जरुर एक उम्मीद जगाई। किन्तु जिस तरह लालू-नीतीश ने बिहार विधानसभा उपचुनाव 'मंडल' की बजाय धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर लड़ा, उससे तय है कि इस लोकतंत्र को सबकी हिस्सेदारी वाला लोकतंत्र बनाने की उनमें भी कोई चाह नहीं है। ऐसे में माया-मुलायम की भांति लालू-नीतीश से कोई उम्मीद रखना भी व्यर्थ है। वैसे मुझे भारी खुशी होगी यदि ये मुझे भ्रान्त साबित कर देते हैं तो।

सारांश में यही कहा जा सकता है कि देश में सुदीर्घतम काल तक शासन करने वाली कांग्रेस ही नहीं,सामाजिक न्याय तथा मुस्लिम राजनीति सहित धूमकेतु की तरह उभरी नई पार्टी 'आप' भी मोदी की सुनामी में क्षत-विक्षत हो गयी। इनमें आप की बर्बादी से भले ही लोकतंत्र प्रेमी बहुजनों को काफी राहत मिली हो किन्तु यह मान लेना ही ठीक रहेगा कि 'आप' के रूप में भारतीय राजनीति में एक लाइलाज वायरस का उदय हो चुका है। मोदी की सुनामी में ध्वस्त हुई कांग्रेस और सामाजिक न्याय की राजनीति का भविष्य पूरी तरह डाइवर्सिटी के अंगीकरण पर ही निर्भर है,यह सत्योद्घाटन भी यह वार्षिकी करती है।

सोलहवीं लोकसभा चुनाव में मोदी की जो सुनामी चली, उसके कारणों पर राजनीति के पंडित लम्बे समय तक बहस चलाते रहेंगे। किन्तु मेरा मानना है कि मोदी की सोशल इंजीनियरिंग इसमें प्रमुख फैक्टर रहा। इस पुस्तक में छपा 'मोदी की सोशल इंजीनियरिंग' नामक लेख इस पर विस्तृत रोशनी डालता है। डॉ. संजय पासवान और रामदास आठवले के बाद राम विलास पासवान, डॉ. उदित राज, उपेन्द्र कुशवाहा, अनुप्रिया पटेल, छेदी पासवान, राम कृपाल यादव, जनक चमार इत्यादि जैसे जनाधार वाले नेताओं का भाजपा के साथ जुड़ना, मोदी के मिशन -272 के लिए एक टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ। हालाँकि मोदी की सोशल इंजीनियरिंग के अतिरिक्त अमित शाह का साम्प्रदायिक कार्ड भी कुछ हद प्रभावी रहा। मेरी यह सोच कितनी सही या गलत है, इस पर राय देने के लिए हमने देश के कुछ प्रतिष्ठित विद्वानों का साक्षात्कार लिया है,जो पाठको को निष्कर्ष पर पहुँचने में सहायक होगा।

मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी

बहरहाल राष्ट्र के जीवन में अच्छे दिन आने की प्रत्याशा जगा कर प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई मोदी सरकार ने सौ दिन पूरे होने का जश्न मना लिया है। इस दरम्यान देश के परम्परागत सुविधासंपन्न तबके ने भले ही अच्छे दिन की आहट महसूस किया हो, किन्तु दबे कुचले जाति के लोगों ने जिस नीची जाति के भावी पीएम को सत्ता में लाया,वह मोदी उनकी प्रत्याशा पूरी करने में अबतक व्यर्थ हैं। मोदी सरकार का पूरा चाल चलन देखकर लग रहा है कि भाजपा अपने पुराने सवर्णवादी

चरित्र से जरा भी नहीं उबर पाई है। उत्तराखंड से शुरु हुआ भाजपा के हार का सिलसिला बिहार तक पहुचने के बाद लगता है कि नीची जाति के लोग भाजपा के मूल चरित्र को समझने लगे हैं इसलिए बड़ी तेजी से वे पिछड़ी जाति के मोदी से मोहमुक्त हुए जा रहे हैं। इस कारण ही सोलहवीं लोकसभा में ध्वस्त हुए सामाजिक न्याय के योद्धा धीरे-धीरे ताकतवर होते जा रहे हैं। यह मोदी सरकार के लिए निश्चय ही खतरे की घंटी है। इसका इलाज 'बिहार विधानसभा चुनाव के सन्देश' नामक लेख में सुझाया गया है।

वैसे तो 2013 के शेष में चार राज्यों के विधानसभा चुनाव से सोलहवीं लोकसभा का जो सेमीफाइनल शुरू हुआ एवं जो 16 मई को तुंग पर पहुंचा, उसको विस्तार से समेटने के बाद इस वार्षिकी में किसी और घटना को जगह देना जरुरी नहीं था। किन्तु 2013 में लोकपाल विधेयक को पारित होने की घटना को नजरंदाज करना कठिन था। लिहाजा हमने इसे वर्तमान इयर बुक में जगह दिया। लोकपाल के मुद्दे पर अपना लेख खास तौर से पढने का आग्रह कर रहा हूँ। इसी तरह जब देश के राजनीतिक दल 16 वीं लोकसभा की तैयारियों में व्यस्त थे, मार्च 2014 में भगाणा की निर्भयाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना घट गयी। यह घटना भी इतनी गंभीर थी कि हम इसके लिए भी एक अध्याय दिए बिना रह सके। यह अध्याय चीख-चीख कर कह रहा है कि देश का चप्पा-चप्पा ही छोटा-बड़ा भगाणा है जहां के दलितों को देश के शक्तिशाली तबकों के अत्याचार से बचाने के लिए एक मात्र उपाय उनकी शक्ति के चप्पे-चप्पे पर भागीदारी है।

श्रद्धांजलि

गत 28 अक्तूबर से राजेन्द्र यादव जैसे मनीषी को खोने के बाद सामाजिक परिवर्तन के एक से एक लोगों को खोने का जो सिलसिला शुरू हुआ वह फिलहाल 22 अगस्त तक आकर रुक गया है। इस दरम्यान हमने राजेन्द्र यादव के बाद ओम प्रकाश वाल्मीकि, नेल्सन मंडेला, प्रभुलाल, नामदेव ढसाल, सुचित्रा सेन, आर. अनुराधा, डॉ. तेज सिंह के बाद यू. आर. अनंतमूर्ति जैसे महान समाज परिवर्तनकामी हस्तियों को खो दिया। इनमें अवश्य ही सुचित्रा सेन और आर. अनुराधा ने सामाजिक परिवर्तन की दिशा में विशेष पहचान नहीं बनाई। किन्तु इन्होंने अपनी जीजीविषा और काबिले मिसाल जीवन शैली की जो अद्‌भुत मिसाल कायम की ,वह बड़े-बड़े महानायकों को भी प्रेरित करती रहेगी। वैसे गत एक वर्ष में हमने नवारुण भट्टाचार्य और मधुकर सिंह जैसे विरल कलमकार व एक्टिविस्टों को खोया है,किन्तु उन्हें इसमें जगह नहीं मिली तो इसलिए कि एक संपादक के रूप में इयर बुक के संपादक मंडली की उपेक्षा कर मैंने अपने पसंद के उन लोगों को जगह दिया जिन्हें बहुत करीब से देखा,सुना व महसूसा था। इनमें सबके साथ समान रूप से न्याय नहीं कर पाने के लिए ग्लानिबोध

हो रहा है। इस लिहाज से जिनके साथ अन्याय हुआ,वे हैं प्रभुलाल,सुचित्रा सेन और खासतौर से यूआर अनंतमूर्ति। जिनके लिए नाम मात्र के पृष्ठ खर्च किये गये हैं। नामदेव ढसाल के लिए कुछ ज्यादा पन्ने खर्च करना भी कईयों को अखर सकता है। इस विषय में यही कहूँगा कि ढसाल साहब बेनजीर थे। उनके जैसा न कोई हुआ है,और न ही होगा। ऐसे विरल महामानव को उपयुक्त श्रद्धांजलि देकर हम खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं।

अंत में। आभारी हूँ उन पत्र-पत्रिकाओं का जिनमें छपे लेखों से इयर बुक : 2014-15 समृद्ध हुई है। आभारी हूँ लेखक बंधुओं का जिनके लेखों और साक्षात्कार के बिना यह अंक बेजान लगता। हर बार की तरह एक बार फिर डाइवर्सिटी मूवमेंट को तन-मन-धन से आगे बढानेवाले मा. बुद्ध शरण 'हंस', डॉ. संजय पासवान, मा. छेदी पासवान, डॉ. विजय कुमार त्रिशरण, मा. दिलीप मंडल, मा. सुरेश केदारे, मा. बृजपाल भारती, मा. ललन कुमार, मा. अभिजित कुमार, डॉ. राजीव, डॉ. राज बहादुर मौर्य, मा. शीलबोधि, मा. सुरेश पंडित, प्रो. आईजे सिंह, मा. नागेन्द्र कुमार, डॉ. कौलेश्वर प्रियदर्शी, मा. निर्मल पासवान, मा. आशिक भागलपुरी, डॉ. सुदर्शन, इंजी. हरिकेश्वर राम, इंजी. हीरालाल, मा. वीके पाल को अशेष धन्यवाद, जिनके सहयोग से नियमित अंतराल पर डाइवर्सिटी साहित्य लोगों के बीच पहुँच रहा है।

!! जय भीम-जय भारत !!

नौवां डाइवर्सिटी डे
(11 अक्टूबर, 2014)

एच.एल. दुसाध
(संपादक, डाइवर्सिटी इयर बुक)

अनुक्रम

सम्पादकीय 5

अध्याय-1

मिशन डाइवर्सिटी

आठवां 'डाइवर्सिटी डे' : फ्लॉप फिर भी खास रहा—*एच.एल. दुसाध* 31
एक और डाइवर्सिटी डे—*एच.एल. दुसाध* 35
मानव जाति को कांशीराम का सबसे बड़ा
उपहार : जिसकी जितनी संख्या भारी...—*शीलबोधि* 38
भगाणा की निर्भयाएं पुस्तक का विमोचन—*दिनेश कुमार* 41
दलित उत्पीड़न का एकमेव प्रतिकार : डाइवर्सिटी-1—*एच.एल. दुसाध* 45
दलित उत्पीड़न का एकमेव प्रतिकार : डाइवर्सिटी-2—*एच.एल. दुसाध* 48
आरक्षण : लोकतंत्र का स्थायी भाव—*अरुण कुमार त्रिपाठी* 51
दलित ईसाइयों को आरक्षण नहीं, डायवर्सिटी की दरकार—*आर.एल.फ्रांसिस* 55
मुस्लिमों को आरक्षण, संविधान और समानता के तकाजे—*प्रो. फैजान मुस्तफा* 59
मलाईदार परतें होनी चाहिए पिछड़े वर्गों में—*चन्द्र भान प्रसाद* 62

अध्याय-2

मोदी के नाम : लोकसभा चुनाव-2014

अध्याय-2 ए : सोलहवीं लोकसभा चुनाव के मुद्दे

लोकसभा चुनाव-2014 के मुद्दे और डाइवर्सिटी—*एच.एल. दुसाध* 67
साम्प्रदायिक ताकतों को शिकस्त देने की तैयारी में जुट
गए हैं नेताजी—*एच.एल. दुसाध* 73
अभी भी कायम है मुल्ला मुलायम का जलवा—*एच.एल. दुसाध* 75
लोकसभा चुनाव-2014 और आधी आबादी का मुद्दा—*एच.एल. दुसाध* 77
उम्मीद की किरण : सोशल मीडिया—*एच.एल. दुसाध* 80
विविधता में व्याप्त शत्रुता का कुफल—*एच.एल. दुसाध* 83
लोकसभा चुनाव-2014 में क्या हो बहुजन
बुद्धिजीवियों की रणनीति!—*एच.एल. दुसाध* 86
क्या भाजपा के घोषणापत्र में बरकरार रहेगा
डाइवर्सिटी का मुद्दा! —*एच.एल. दुसाध* 95

हम एक हैं : भाजपा-कांग्रेस—*एच.एल. दुसाध* 98
संकट में सामाजिक न्याय की राजनीति—*एच.एल. दुसाध* 101
लोकसभा चुनाव : मुद्दा सामाजिक और लैंगिक विविधता का—*एच.एल. दुसाध* 105
काशी संसदीय क्षेत्र में एनजीओ गैंग के सरगना के उतरने
पर दुसाध की अपील—*एच.एल. दुसाध* 108
लोकतंत्र को बचाने के लिए दूरगामी रणनीति की जरूरत—*एच.एल. दुसाध* 115
निचले पायदान पर सामाजिक न्याय का मुद्दा—*एच.एल. दुसाध* 118
मतदान केन्द्रों पर बढ़ती भीड़ : कमजोर पड़ती—*एच.एल. दुसाध*
जातिवादी राजनीति का परिणाम—*एच.एल. दुसाध* 121
विविधता विरोधी मोदीफेस्टो—*एच.एल. दुसाध* 124
चुनावी मैदान में पेशेवरों की भीड़ का निहिताथ—*एच.एल. दुसाध* 130
अध्याय-2 बी : मोदी के नाम सोलहवां लोकसभा चुनाव
महानायक मोदी—*अश्विनी कुमार* 133
हर हर मोदी-घर घर मोदी—*बाल मुकुन्द ओझा* 135
मन्दिर मुद्दे से आगे निकल गई मोदी लहर—*अखिलेश वाजपेयी* 138
मोदी की बयार 140
मोदी की आंधी में उड़े सूबाई क्षत्रप—*सुरेन्द्र प्रताप सिंह* 142
16वीं लोकसभा चुनाव की 16 सुर्खियाँ 144
चार सियासी दलों की 'राष्ट्रीयता' दाँव पर 148
गुजरात में तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बना 'नोटा' 150
अब करेंगे राष्ट्र निर्माण—*राम माधव* 152
1652 दलों को एक भी सीट नहीं मिली 153
नमो नमः—*शत्रुघ्न शर्मा* 154
मोदीमय मीडिया—*सुधीश पिचौरी* 160
राजग का कुनबा 163
ये हैं मोदी के भरोसेमंद 166
जीत गई उम्मीदें हार गईं अटकलें—*रईस अहमद 'लाली'* 173
आखिर किसने जिताया भाजपा को—*मधुकर मिश्र* 176
छोटी पार्टियों ने भी पार की वैतरणी—*पूजा मेहरोत्रा* 180
अब होगा 'मोदी मैजिक' का असली इम्तहान—*मधुकर मिश्र* 182
क्या मोदी ने भारत जीत लिया?—*हर्षवर्धन तिवारी* 185
मोदी लहर के साथ चली 'मुस्लिम विरोधी लहर'—*समीर किरमानी* 188
दीदी और अम्मा ने वर्चस्व बनाए रखा—*वीरेन्द्र शर्मा* 190
मोदी की आहट से कई राज्य सरकारें घबराईं—*ललित पांडे* 193

खूब दौड़ी बदजबानी एक्सप्रेस—*स्वतंत्र मिश्र* 196
झामुमो ने बचाया किला, मुंडा ने जताई अपनी पकड़—*अशोक रंजन* 198
अब शुरू होगी कांग्रेस की सर्जरी—*सोमरत शास्त्री* 200
भाजपा ने किया सूपड़ा साफ—*अवधेश अकोदिया* 203
नई सरकार पर होगी संघ की खास नजर—*सुधीर जोशी* 205
अध्याय-2 सी : मोदी सरकार का एजेंडा
मोदी की सोशल इंजीनियरिंग—*एच.एल. दुसाध* 208
लौटना होगा कांशीराम के भागीदारी दर्शन की ओर—*एच.एल. दुसाध* 211
भयावह विषमता और अच्छे दिन—*एच.एल. दुसाध* 214
पुरस्कार से वंचित मोदी के अस्पृश्यतामोचक—*एच.एल. दुसाध* 217
मोदी के एजेंडे में कहां हैं दलित—*एच.एल. दुसाध* 223
भाजपा का दायित्व-भाव और दलित—*एच.एल. दुसाध* 229
अध्याय-3
मोदी सुनामी में उड़ी कांग्रेस
अध्याय-3 ए : कांग्रेस की अभूतपूर्व पराजय
कांग्रेस को हर दांव पड़ा उल्टा 235
बेटे को बचाने फिर आगे आईं सोनिया 237
हार की समीक्षा करने वाली कमेटियों से भी हार गई कांग्रेस 238
प्रियंका लाओ, कांग्रेस बचाओ 240
माँ-बेटे की भेंट चढ़ी कांग्रेस—*अश्विनी कुमार* 241
पार्टी की हार से उपजा सवालों का पहाड़ 243
टूट भी सकती है कांग्रेस—*नीरजा चौधरी* 245
अकेला पड़ गया हाथ, नहीं मिला साथ—*सरोज नागी* 247
अब तुम्हारे हवाले वतन साथियो!—*डॉ. दर्शन सिंह हरविंदर* 250
राहुल क्यों हारे, प्रियंका क्या करेंगी!—*राजकिशोर* 254
कहीं अपने ही न छोड़ दें हाथ का साथ!—*रणविजय सिंह* 256
तो क्या कांग्रेस युग का अंत हो गया है?—*अरुणा सिंह* 259
अन्दरूनी लड़ाई में ढही कांग्रेस—*अन्तत विजय* 263
कैसे उबरेंगे राहुल गांधी—*अजय एन झा* 266
अध्याय-3 : बी कैसे हो कांग्रेस का पुनरुद्धार!
कुनबे को बचाना चुनौती—*इंदर मल्होत्रा* 268
घिरता अन्धकार, साथ छोड़ते साए—*अरविन्द मोहन* 270
कांग्रेस के भविष्य की राह—*आशुतोष मिश्र* 273
कठिन राह पर कांग्रेस—*डॉ. निरंजन कुमार* 276

Continue Your Reading Journey

This preview has ended. Access the complete library and support our mission.

Join Our Inclusive Reading Community

✓ We champion diverse voices and perspectives
✓ Your support helps amplify underrepresented authors
✓ We provide free access to educational institutions
✓ Building bridges through shared stories
✓ Creating space for all narratives to be heard

Support Our Mission

Your donation enables us to:
• Curate diverse book collections
• Support authors from marginalized communities
• Provide free resources to educators
• Maintain our accessible digital library

Visit: www.diversitymission.in

Sign the diversity pledge • Make a donation • Download full library